(संशोधित)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष / फैक्स नं0 05947—251362

पत्रांक 2997/ 12-1 दिनांक, 17 /05/ 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः— जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में संशोधित आख्या ।

संदर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1849 / 12—1 दिनांक 26.02.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी 3 बिन्दुओं पर सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित की जा रही है:—

1. **For what propvision lease was sanctioned?:-** उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है की सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की शा0दे0सं0 1983 / 14—2—78 / 74 दिनांक 03.07.1975**(संलग्न—1)** से श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर में रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे प्लॉट सं0 08 एवं 09 की 2700 वर्गफी0 वन भूमि 30 वर्षो के लिए लीज पर दिये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। परन्तु लीजधारक द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.03.78 के माध्यम से लीज भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालन करने हेतु अनुमति चाही गयी। जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 6374 / 14—2—578 / 74 दिनांक 26.08.1978**(संलग्न—2)** के माध्यम से सचिव, उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा अनापत्ति जारी की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि:—

   " यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से " नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट" प्राप्त कर लेते है तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र(Agricultural implements workshop) के स्थपनार्थ शासनादेश संख्या 1983 / 14—2—78 / 74 दिनांक 03.07.1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।"

   इस प्रकार लीजधारक को प्रश्नगत लीज भूमि पर कृषि सेवा केन्द्र(Agricultural implements workshop) के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी।

2. **Is there any violation of lease deed?** लीजधारक द्वारा प्रश्नगत लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है, कृषि सेवा केन्द्र का निर्माण नही किया गया है।

   साथ ही लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया है की भारत सरकार द्वारा बेरोजगार इन्जीनियरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों का खुलवाया गया था। परन्तु इस स्कीम के असफल होने के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार द्वारा समिति बनाई गयी, जिसने असफलता के कारणों को देखते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए इनके पुनर्वास की अनुशंसा की गई थी, तब भारत सरकार ने तत्कालीन लोकसभा में भी इन इन्जीनियरों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री की सहमति से प्रभावित इन्जीनियरों को पेट्रोल उत्पादन की पेट्रोल पम्प की डीलरशिप देने आदि के लिए साक्षात्कार के द्वारा आवंटन किया गया। (छायाप्रति संलग्न—3)

3. **Lease originaly was granted till 2005. Why it has not been renewed after2005?** इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार लीजधारक द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु प्रथम आवेदन वर्ष 2008 में उनके पत्र दिनांक 22.02.2008(संलग्न–4) द्वारा किया गया था। जिसके उपरान्त उनके द्वारा पुनः पत्राचार वर्ष 2013(संलग्न–5) में किया गया, जिसके क्रम में लीजधारक को लीज नवीनकरण प्रस्ताव गठित कर उलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 05.09.2019 को प्रस्ताव आनलाईन माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात समय–समय पर विभिन्न स्तर से लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु पत्रचार अतिथि तक गतिमान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है की शा0सं0 1963/14–2–78/74 दिनांक 03.07.1975 की बिन्दु सं0 3 में स्पष्ट किया गया है की:–

" कृपया विलेख का आलेख्य शासन के अनुमोदनार्थ भेज दें एवं पट्टेदार को निदेश दें कि वे 32 रू0 विधीक्षण शुल्क के रूप में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा करके ट्रैजरी चालान गवर्नमेन्ट कन्वेयेन्सर, उ0प्र0 विधान भवन लखनऊ के पास भेज दें–

"065 अन्य सामान्य सेवायें–क–अन्य प्रशासन –I – सेवायें तथा सेवा शुल्क निजी निकायों के लिये काम करने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस" "

1. उपरोक्त शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है की इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पट्टाविलेख तैयार नहीं किया गया है।
2. उक्त लीज वर्ष 2005 तक स्वीकृत थी, जिसके नवीनीकरण हेतु लीजधारक द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम पत्राचार किया गया। वर्तमान तक लीज नवीनीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में FCA 1980 के प्रावधानों के तहत उक्त लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है।
3. उक्त लीज हेतु लीज रेन्ट वर्ष 2005 तक जमा किया गया है। प्रश्नगत लीज के नवीनीकरण हेतु लीज रेन्ट का आगणन जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 03/5–स्टाम्प/मूल्यांकन–2022–23(संशोधित दर सूची) दिनांक 16.02.2023(संलग्न–6) के द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर के अनुसार निम्न प्रकार किया गया है:–

भूमि का मूल्य 1मी0² के लिए वर्तमान बजार दर के अनुसार	= रू0 47750.00/1मी0² = रू0 47,75,00,000.00/है0
प्रश्नगत लीज नवीनीकरण में प्रस्तावित 0.0250 है0 भूमि का मूल्य	= 0.0250 X रू0 47,75,00,000.00/है0 = रू0 1,19,37,500.00/–
उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या 1125/X-3-21/02(04)/2018 दिनांक 14.09.2021 के प्रस्तर 3.1.4 के अनुसार प्रीमियम	= जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर X लीज अवधि/90 = रू0 1,19,37,500.00 X 30/90 = रू0 39,79,167.00/–
उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या 1125/X-3-21/02(04)/2018 दिनांक 14.09.2021 के प्रस्तर 3.1.4 के अनुसार वार्षिक लीज रेन्ट	= प्रीमियम का 5% = रू0 198,958.00/–
उपरोक्तानुसार दिनांक 04.07.2005 से आतिथि तक 19 वर्षों का बकाय वार्षिक लीज रेन्ट	= 19 वर्ष X रू0 198,958.00/– = रू0 37,80,202.00/–
कुल धनराशि	= प्रीमियम + 19 वर्षों का बकाय वार्षिक लीज रेन्ट = रू0 39,79,167/– + रू0 37,80,202/– = रू0 77,59,369.00

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत लीज नवीनीकरण हेतु कुल धनराशि रू0 77,59,369.00 (सतहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ उनहत्तर रूपये मात्र/–) लीज धारक से अपेक्षित है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिव्य नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(दिव्य नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रतिलिपि शा0 सं0 1963/14=2=78/74 दिनांक 3=7=75 प्रेषक, सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ सेवा में, आयुक्त, प0वृ0 उ0प्र0 नैनीताल ।

=====

विषय :- श्री हरीश चन्द्र धिलियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वन भूमि दिया जाना ।

=====

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0 2673/5=2 (T) दिनांक 3 मार्च 1975 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने श्री हरीश चन्द्र धिलियाल को कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural Implements workshop) के स्थापनार्थ रामनगर — [illegible] मंदिर मार्ग के किनारे 2700 वर्ग फीट (प्लाट नं0 8=1425 वर्ग फीट एवं प्लाट नं0 9=1275 वर्ग फीट) भूमि निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है :-

1. पट्टेदार उक्त भूमि का 7,500रु0 प्रीमियम एवं 375 रु0 वार्षिक किराया देगा ।
2. पट्टे की अवधि 30 वर्ष की होगी ।
3. भूमि जिस प्रयोजन के लिये दी जा रही है केवल उसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जायगी । पट्टेदार की पट्टे पर स्वीकृत भूमि की आवश्यकता न रहने पर वह बिना कोई प्रतिकर दिये ही वन विभाग को वापस हो जायगी ।
4. पट्टेदार उक्त भूमि को किसी को भी किसी भी रूप में हस्तान्तरित न कर सकेगा ।
5. यदि एक वर्ष के भीतर पट्टेदार द्वारा उक्त केन्द्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया जाता है तो उक्त भूमि बिना कोई प्रतिकर दिये ही शासन द्वारा वापस ले ली जायगी ।
6. यदि सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना हेतु दी गई अनुज्ञा वापिस ले ली जायगी तो पट्टा भी उसी समय से रद्द माना जायेगा ।
7. पट्टे की अवधि की समाप्ति पर अथवा शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप पट्टा रद्द किये जाने पर उक्त वन भूमि बिना कोई प्रतिकर दिये ही शासन को वापस हो जायगी एवं पट्टेदार को दो माह का समय दिया जायेगा जिसके भीतर वे अपना समस्त सामान एवं निर्माण कार्य आदि हटा लें अन्यथा । उक्त समय के बाद जो भी सामान प्रश्नगत भूमि में रहेगा

जायगा वह सरकार की संपत्ति हो जायगी जिसके लिये पट्टेदार किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

2. प्राप्त धनराशि आय-व्ययक के प्राप्ति शीर्षक '' 113- वन '' के मूल उप शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जाय ।

3. कृपया विलेख का आलेख्य शासन के अनुमोदनार्थ भेजिये एवं पट्टेदार को निर्देश दें कि वे 32 रु0 विधायन शुल्क के रूप में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा करके ट्रेजरी चालान गवर्नमेन्ट कन्वेयेन्सर, उ0प्र0 विधान भवन लखनऊ के पास भेज दें :-

"065 अन्य सामान्य सेवायें - क - अन्य प्रशासन -।- सेवायें तथा सेवा शुल्क किसी निकायों के लिये काम करने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस ''

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है जो उनके अशासकीय सं0 ई - 7= 1431/दस- 75 दिनांक 27=6=75 द्वारा प्रदत्त है ।

=====

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 7

आज्ञा से,

ह0 एन0 पी0 त्रिपाठी
सचिव ।

कार्यालय अति0 मुख्य वनसंरक्षक, कु0 उ0प्र0 नैनीताल ।

सं0 ट- 320/5=2 रा. (H.) दिनांक नैनीताल जुलाई 3/ 1975

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को उनके पत्र सं0 2500/5=4 दिनांक 7=2=1975 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । शासनादेश के पैरा 3 पर शीघ्र कार्यवाही करें ।

अग्रेषित

(देवेन्द्र प्रसाद जोशी)
अति0 मुख्य वन संरक्षक, कु0 उ0प्र0
नैनीताल ।

सं. 168 प्रतिलिपि ... दिनांक ...8-75

(50)

प्रतिलिपि शासनादेश संख्या 6371/14-2-578/74, लखनऊ, दिनांक, जून 26, 1978 वन अनुभाग-2, प्रेषक श्री एन०पी० त्रिपाठी, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

विषय:- श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वन भूमि दिया जाना।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6378/5-2 रा०, दिनांक जून 16, 1978 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "नौ आब्जेक्शन सर्टीफिकेट" प्राप्त कर लेते है तो उन्हे कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural implements workshop) के स्थापनार्थ शासनादेश संख्या 1963/14-2-578/84, दिनांक जुलाई 3, 1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नही है।

362 5-4 15/7 "A"

कार्यालय अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, उत्तर-प्रदेश, नैनीताल। 12

पत्र संख्या 17738 / 5-2(R) दिनांक: नैनीताल, जुलाई 78

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को इस कार्यालय के पृ० ज्ञापन संख्या 6378/5-2 (रा०) दिनांक 16-6-78 के क्रम में सूचनार्थ एवं उक्त शासनादेशानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

(आर०बी० माथुर) 10/7
अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, उ०प्र०,
नैनीताल। 10/7

वि/19

विषय:- पेट्रोल तथा डीजल पम्प खोलने की अनुमति चाहने हेतु।

प्रसंग - इस कार्यालय का पत्र सं. 3843/5-4 दि. 14-4-78.

कृपया आपेक्षित नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

प्र० वना०

(3) (7)

(9) Pages

REVISED DRAFT

SCHEME

FOR

REHABILITATION

OF

SICK AGRO SERVICE CENTRES

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1238

TO BE ANSWERED ON THE 1ST MARCH, 1982

DECLINE OF AGRO-SERVICE CENTRES

1238. SHRI B.D. SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of agro-service centres in the country are in [illegible] and that more than 500 such centres have been closed down while many are on the verge of bankruptcy; and

(b) if so, details thereof alongwith the reasons therefor and the step taken by Government to improve the situation?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

(SHRI R.V. SWAMINATHAN)

(a) As per the survey conducted by the Central Govt. Training Centres at Budni and Hissar in the year 1977 covering the States of Assam, Bihar, Haryana, J & K, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, 75% of the agro-service centres were operating on profit and 25% alone as not doing well. Subsequent survey carried out by the Tractor Training Centre, Hissar in 1978 revealed that 67.5 % agro-service centres on an average were running on profit whereas 19.8% were working on loss. The remaining 12.7% did not report their financial benefits. As on 21st March, 1981 506 out of 3206 centres(i.e. 15.8%) have closed down. The Government, however, have no information to lead to the conclusion that many of these centres are on the verge of bankruptcy.

(b) Details:- State-wise position of break-up of 508 centres reported to have been closed is given in annexure.

Reasons for the failure :

As per the survey carried out in 1977 the reasons for failure of closing down of some of these centres was low work turn over because of their being engaged only in the activity of custom hiring in tractors accompanied by competition from tractor- owning farmers, escalation in the operational cost of these machines due to hike in the prices of diesel and other lubricants and other raw materials, high cost of these machines, escalation in the cost of repair and maintenance, non-maintenance of proper records about their working, lack of requisite efforts on the part of entrepreneurs to improve their performance etc.

Steps taken by the Government to improve the situation :-

The steps taken by the Government to improve performance and financial viability of these centres are details below :-

i) These agro-service centres were given priority allotment of tractors both indigenous and imported.

ii) The RBI on our initiative have extended the benefits of concessional rate of interest to these agro- service centres on par with small scale industries and credit guarantee cover.

contd P.O.

(3) Pages

iii) At various stages seminars and meetings [illegible] the performance of these centres when [illegible] advised to diversify their business on [illegible] as per the local demands and not confine [illegible] hiring of tractors alone.

iv) The Ministry of Finance advised the RBI to [illegible] to the nationalised banks to rephase the payment [illegible] instalments of bank loans taken by them [illegible]

v) On transfer of the scheme to the State [illegible] the States were directed to honour the commit[illegible] transfer and to extend such other necess[illegible] required for running them on viable basis.

vi) Minister of State for Agriculture addressed [illegible] Ministers concerned to take such steps as would be [illegible] strengthening these centres, including expenditure [illegible] the claims of these agro-service entrepreneurs [illegible] subsidy.

vii) Minister(A, RD& CS) once again addressed the Chief [illegible] of the States to take action to disburse the interest [illegible] these entrepreneurs urgently, to route the distribution [illegible] agricultural inputs in the areas where these centres [illegible] through them to help them in getting custom [illegible] in the various schemes implemented by the State [illegible] their various programmes including programmes of [illegible] and command area development. Simultaneously he addressed the Union Finance Minister of instruct the Commercial [illegible] interest charges on loans advanced to these centres and [illegible] the payment of principle amount. Union Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers was also addressed by him to consider the case of these centres for allotment of d[illegible] petrol and petro-based lubricants.

Note:- AT THE SUPREME COURT : The Agricul[illegible] in the Parliament, but not in the Supreme Court [illegible] say that the Government may not submit a report [illegible] means that our case may be posted for arguments [illegible] the latest counter by SBI in Maharashtra [illegible] formidable one against us. Sri Nariman [illegible] to file such counters even in previous [illegible] asked for Petitioner-wise/ Writ-wise/ State-[illegible] So please send your latest full information

***

INDEX

Page Number

1.	Name of the Scheme	:	1
2.	Objective of the Scheme	:	1
3.	Eligibility Criteria	:	1
4.	Components of the Scheme	:	
	4.1 Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to non viable Agro Service Centres which can not be Rehabilitated.	:	2
	4.2 Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to potentially viable Agro Service Centres which can be rehabilitated.	:	4
	4.3 Other assistance to be extended to identified sick agro service centres	:	5
5.	Implementation procedure	:	7

1. Name of the Scheme : Rehabilitation of Sick Agro Service Centres (ASCs).

2. Objective of the Scheme : The Scheme aims at rehabilitation/revival of the identified sick Agro Service Centres set up under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme which was operated through Agro Industries Corporations at the State Level during the period 1971 to 1979 and later transferred to State sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.

3. Eligibility Criteria

3.1: The Scheme will be confined to ASCs which were opened under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme launched in Dec., 1971 and later transferred to State Sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.

3.2 ASCs whose owners have not migrated out of the country.

3.3 The agro-entrepreneurs who have taken up alternative employment, may also be considered for assistance, provided the units are found viable and the entrepreneurs agree to run the units themselve.

3.4 The agro-entrepreneurs who have sold their assests will not be considered eligible for any assistance under the scheme.

3.5 Agro-Entrepreneurs who have been wilful defaulters in the past will not be eligible for any assistance under the Scheme.

4. Components of the Scheme : Under the Scheme, the agro-entrepreneurs will be provided reliefs and concessions on the following pattern.

4.1 [illegible] to be taken [illegible] ect of non-vi[illegible] Agro Service [illegible] which [illegible] be rehabili-[illegible]

4.1.1 Bank will consider each case on merits and the normal steps for the recovery of bank dues will be initiated.

...2/-

4.2 **Reliefs and concessions which can be extended by banks/Financial Institutions to potentially viable Agro Service Centres which can be rehabilitated.**

4.2.1 **Penal interest and funded interest** : If penal rates of interest or damages have been charged such charges should be waived from the accounting year of the unit in which it started incurring cash losses continuously. After this is done, the unpaid interest on term loans and cash credit during this period should be segregated from the total liability and funded. No interest may be charged on funded interest and repayment of such funded interest shall be payable in 5 years from the date of commencement of implementation of the rehabilitation programme.

4.2.2 **Unadjusted interest dues** : Unadjusted interest dues such as interest charged between the date upto which rehabilitation package was prepared and the date from which actually implemented, may also be funded on the same terms as 4.2.1 above.

4.2.3 Term loans The rate of interest on term loans may be reduced, where considered necessary, by not more than three percent, the reduced rate, in no case being less than the rate of interest charged under Integrated Rural Development Programme (IRDP).

4.2.4 **Principal dues** After the unadjusted interest portion of the cash credit account [illegible] as indicated in 4.2.1 and 4.2.2 above, the balance representing principal dues may be..

treated as irregular to the extent it exceeds drawing power. This amount may be funded as Working Capital Term Loan (WCTL) with a repayment schedule not exceeding 5 years. Interest may be charged on this funded item at 10 percent per annum.

4.2.5 <u>Cash Losses</u>

Cash losses are likely to be incurred in the initial stages of the rehabilitation programme till the unit reaches the break even level. Such cash losses excluding interest as may be incurred during the nursing programme may also be financed by the bank or the financial institution, if only one of them is the financier. But if both are involved in the rehabilitation package, the financial institution concerned should finance such cash losses Interest may be charged on the funded amount at the rates prescribed by IDBI under its scheme for rehabilitation assistance.

4.2.6 <u>Working Capital</u>

Need-based working capital should be sanctioned to the unit to enable it to carry on its operations, with interest at the minimum of the band of the prescribed interest rates during the rehabilitation period. Where the minimum of the band exceeds 15% (as for instance in the case of working capital assistance in excess of Rs.25 lakhs, where it is 16.5%), the rate may be fixed at 15% per annum.

4.2.7 <u>Contingency loan assistance</u>

For meeting escalations in capital expenditure to be incurred under the rehabilitation programme, banks/financial Institutions may provide, where considered necessary, appropriate additional financial assistance upto 15% of the estimated cost of rehabilitation by way of contingency loan assistance. Interest on this contingency assistance may be charged at the concessional rate allowed for working capital assistance.

4.2.8. <u>Funds for start-up expenses and margin for working capital</u>

There may be a need to provide the unit under rehabilitation with funds for start-up expenses (including payment of pressing creditors) or margin...

money for working capital in the form of long-term loans. Where a financial Institution is not involved, banks may provide the loan for start-up expenses, while margin money assistance should be provided by State Government where it is [illegible]. The [illegible] loan from banks will carry the same rates as the existing term loans.

4.2.9 Guarantee fee

The guarantee fee payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) in respect of sick agro-service Centres units should be borne by the Banks/Financial Institutions during the period of rehabilitation programme.

4.3 Other assistance to be extended to identified sick agro service centres.

4.3.1 Accommodations

State Governments will consider requirements of agro-entrepreneurs on case to case basis, for allotment of suitable accommodation at nominal charge, if such a measure has been recommended by District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the sick agro service centre concerned.

4.3.2 Agriculture Inputs distribution

State Governments and State Agro-Industries Corporations will accord priority to the identified sick agro service centres in matters of giving agencies for input distribution, if such measure, has been recommended by the District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the agro service centre concerned. States may consider adopting the Maharashtra pattern in this regard. States may also designate ASCs as approved outlets for items in which cooperative do not deal in.

contd..5/-

4.5 Pending claims of Interest subsidy

State Governments will be requested to process and make payment of pending interest subsidy claims, if any, of the agro enterpreneurs in accordance with the provisions of the agro service centres scheme transferred to States w.e.f. 1.4.79 in persuance to the decision of National Development Council.

Implementation procedure.

5.1 The State AICs will be responsible for identification of eligible agro service centres as per the eligibility criterial as in para 3 above. After the approval of the rehabilitation scheme by Supreme Court of India, the Agro-Entrepreneurs shall submit their applications alongwith rehabilitation proposal for consideration to the concern State Agro Industries Corporation within 90days of the order of the Supreme Court. The State Agro Industries Corporation will scrutinise the applications received, within a period of 30 days from the date of its receipt and forward the same to the District Level Appraisal Committee(DLAC).

5.2 Rehabilitation proposal as in 5.1 above will be considered by the District Level Appraisal Committee constituted as under

(i) Distt. Collector -Chairman.
(ii) One representative of Lead Bank. -Member
(iii) One representative of Creditor Bank. -Member
(iv) Representative of the Managing Director of State Agro Industries Corporations. -Member-Secretary.

The proposals for rehabilitation considered viable will be recommended by the DLAC to the concerned Bank for [illegible]. Proposals

6.

for rehabilitation not considered viable shall be rejected by the DLAC and the dues of the Bank/Financial Institution shall be recovered in such instalments as may be decided by the Bank/Financial Institution on merits of each case.

The DLAC will also review the progress of each case on quarterly basis and submit the report to the Chairman of the Task Force.

3. For monitoring and periodical review of the progress and removal of constraints etc, a Task Force will be set up in each of the concerned State as under:-

i)	Secretary(Agri.)	: Chairman
ii)	One Representative of Lending Bank	: Member
iii)	One representative of Reserve Bank of India.	: Member
iv)	One representative of NABARD	: Member
v)	One representative of Small Industries Service Institute	: Member
vi)	Two representatives of agro-entrepreneurs.	: Member
vii)	Managing Director of State Agro Industries Corporation.	: Member Secretary

The representative of the agro-entrepreneurs will be selected in a meeting of such entrepreneurs, financed under the Centrally Sponsored Scheme of Agro Service Centres, held by the State Agro Industries Corporation under the Chairmanship of the Managing Director of the Corporation.

contd...7/-

The Task Force would periodically review and monitor the progress of the scheme and submit a quarterly report to the Government of India in the Ministry of Agriculture.

5.4

5.4 A National Level Committee to review and monitor the progress of rehabilitation scheme shall be constituted. This Committee shall consist of representatives of all concerned Ministries of Government of India, RBI, IBA, all concerned Commercial Banks, State Governments, SAICs and two representatives of National Federation of Agro Entrepreneurs.

The delay in implementation of the Scheme will be reviewed by District Level Committee periodically. One of the factors contributing to such delays could be time taken for obtaining clearance to the reliefs and concessions. The banks and the financial institutions will delegate sufficient powers to senior officers at various levels such as district, divisional, regional, zonal and also at head office to sanction the banks or the financial institutions commitment to its share in the rehabilitation proposal drawn up in conformity with the Scheme approved by the Supreme Court of India and the prescribed guidelines/Instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time.

AGRO SERVICES & FILLING CENTRE

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.

RANIKHET ROAD, RAMNAGAR (NAINITAL) ☎ (05945) RESI. 85523, OFF. 85484

Ref. No.

Date 22-02-1998

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग रामनगर।

विषय- प्लाट संख्या क्र० 9 के लीज नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि फर्म का प्लाट संख्या क्र० 9 का लीज नवीनीकरण होना है। अतः आप लीज नवीनीकरण करने की अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(हरीश चन्द्र घिल्डियाल)

एग्रो सर्विस एण्ड फिलिंग

सेन्टर [illegible]

रानीखेत रोड रामनगर

(नैनीताल)

AGRO SERVICES & FILLING CENTRE

Dealer: INDIAN OIL CORPORATION LTD.

RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)

(05947) OFF.-251484, RESI.-251523

Ref. No. .... Date..............................

To,
The DFO, Ramnagar
Uttarakhand

Date: 05/08/2013

Subject: Renewal of the lease for plot no 8 & 9, on Ranikhet Road, Ramnagar, on name of Harish Chandra Ghildiyal

Dear Sir,

This is to request you to renew the lease of plot no 8 & 9 on Ranikhet Road which was allotted to Harish Chandra Ghildiyal S/o Late Shri M N Ghildiyal. This plot has office of Adarsh Cooperative transport on North, Forest compound on west and Ranikhet Road on East; since the allotment of lease, Agro Services & Filling Center (petrol pump) has been operating on this plot.

I would request you to kindly renew the lease of plot not 8 & 9 to Harish Chandra Ghildiyal to whom this plot was originally allotted.

Thanks and Regards

Harish Chandra Ghildiyal
Prop Agro Services and Filling Center
Ranikhet Road
Ramnagar (nt)
Uttarakhand

6/8/13

कार्यालय जिलाधिकारी / कलेक्टर नैनीताल

दिनांक 16 फरवरी 2023

पत्रांक 03 / 5–स्टाम्प / मूल्यांकन–2022–23(संशोधित दर सूची)

केन्द्रीय मूल्यांकन समिति की संस्तुति के पश्चात शासन के पत्र संख्या 615 / 2023 / XXVII(9) / स्टाम्प 80 / 2009 दिनांक 15 फरवरी 2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद नैनीताल से संबंधित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदित मूल्यांकन सूची दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी दर सूची को संशोधित किया जाता है जो दिनांक 16 फरवरी 2023 से प्रभावी होगी।

(धीराज गर्ब्याल)
जिलाधिकारी
नैनीताल

जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के प्रमुख मार्गो पर स्थित क्षेत्र की सर्किल दरें

क्र0 सं0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्ला/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग /मोहल्लों/राजस्व ग्रामों के नाम		सामान्य दर (Base Rate) कृषि भूमि की दर (प्रति हैक्टेयर लाख रु0 में)	अकृषि भूमि की दर (प्रति वर्गमीटर रु0 में)		बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु0 में)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु0 में)		गैर वाणिज्यिक निर्माण दर (रु0 प्रति वर्गमीटर में)	
				0 से 200 मीटर तक	0 से 50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मीटर तक		दुकान रेस्टोरेन्ट कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी टिनशेड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A	रामनगर–रानीखेत मुख्य मोटर मार्ग पैठपडाव से मोहान तक (वाया ढिकुली)									
		1	मोहल्ला रानीखेत रोड (वार्ड नं0 20)	980	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
	A (I)	1	लखनपुर (वार्ड नं0 04)	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
		2	पैठपडाव (वार्ड नं0 20)	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
		3	टेढ़ा रोड (वार्ड नं. 03)	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
	A (II)	1	दुर्गापुरी (वार्ड नं0 02)	980	12000	10500	24000	41700	37200	12000	7000
		2	ढिकुली	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
		3	लदुवाचौड़	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
		4	मोहान	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
		5	लटूवारी	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
		6	अमरपुर	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
2	B	रामनगर–काशीपुर मुख्य मोटर मार्ग काशीपुर रोड से भवानी गंज तक									
		1	काशीपुर रोड (वार्ड नं. 13)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		2	जसपुरीया लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		3	भवानी गंज (वार्ड नं. 17)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
3	C	रामनगर नगर पालिका क्षेत्र/वार्ड कसेरा लाईन से ऊंटपडाव तक वाया रानीखेत रोड									
		1	कसेरा लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		2	ज्वाला लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		3	नन्दा लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		4	बजाजा लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		5	कोसी रोड (वार्ड न. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000